BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया बुधवार विक्रम संवत् 2079। 01 जून 2022

JKDESIGN 8369994118

6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

पॉलिसी . बिहार की अर्थव्यवस्था में जान फूंकेगा मक्का

किसानों की जेब में इथेनॉल से प्रति वर्ष आयेंगे ढाई हजार करोड़ रुपये

प्रभात खबर विशेष

राजदेव पांडेय ▷ पटना

इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में अगले दो साल में 30 हजार करोड़ से अधिक के निवेश आये हैं. इस निवेश से निवेशकों का पैसा तो बनेगा ही, किसानों की भी चांदी होगी. इथेनॉल के ग्रीन फील्ड ग्रेन प्लांट लगने के मक्का उत्पादक किसानों के दिन फिरने जा रहे हैं. वह इसलिए कि इथेनॉल उत्पादन का मुख्य कच्चा माल इकलौता मक्का है. अनुमान के मुताबिक सालाना ढाई हजार करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में जायेगी.बिहार में मक्का का उत्पादन 35 लाख टन वार्षिक से अधिक है. उत्पादन में सालाना पांच फीसदी की वृद्धि है. इथेनॉल प्लांट्स जैसे-जैसे धरातल पर उतरेंगे, मक्का नकदी फसल (कैश क्रॉप) में बदल जायेगा. मक्का उत्पादक लाखों किसानों को फायदा होगा. बिहार में धान के बाद यही एक ऐसी फसल है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर है. बिहार में पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में हाल में चालू हुआ है. मक्का के अलावा टूटे चावल से इथेनॉल बनाने की अनुमति प्रदेश में दी गयी है. कच्चे माल की उपलब्धता के हिसाब से मक्का सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला वस्तु है. इस तरह धान बड़ी व्यापारिक फसल के रूप में उभर सकता है.उद्योग विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में अगले दो वर्षों में बिहार में 30 हजार करोड़ का निवेश होना तय है. उद्योग विभाग के आर्थिक विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक एक हजार केएलडी (किलो लीटर पर डे) के मक्का आधारित प्लांट से इथेनॉल बनाने पर उद्यमी को मक्का खरीद पर कुल सालाना 109 -125 करोड़ खर्च करने होंगे. एक हजार लीटर के प्लांट के लिए 78 हजार टन सालाना मकई की जरूरत पड़ेगी. मकई की सामान्य कीमत 14 रुपये प्रति किलो है. इस दाम पर किसानों की जेब में 109-125 करोड़ जायेंगे, क्योंकि इथेनॉल की मांग बढ़ते ही मक्का की कीमत उसके घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 से भी अधिक होने की उम्मीद है.

राज्य में 17 प्लांट लगने हैं

बिहार में 17 प्लांट लगने हैं. इनमें अधिकतर एक हजार केएलडी से अधिक के हैं. इस तरह बिहार के किसानों की जेब में ढाई हजार करोड़ से अधिक जाने तय हैं. साथ ही प्लांट संचालन के लिए पावर प्लांट चलाने के लिए निवेशक को धान आदि की भूसी की जरूरत होगी. एक हजार केएलडी के प्लांट के लिए भूसी की सालाना जरूरत 80 हजार टन होगी. इसके लिए राइस मिलर को 32 करोड़ मिलेंगे.

हर प्लांट में सौ को प्रत्यक्ष रोजगार

प्रत्येक प्लांट में प्रत्यक्ष तौर पर सौ लोगों को रोजगार मिलेगा. उद्यमी को करीब तीन से चार करोड़ रुपये उनकी सैलरी पर खर्च करने होंगे. एक हजार केएलडी के प्लांट से साल में 3 .5 करोड़ लीटर इथेनॉल बनेगा. पेट्रोलियम कंपनियां एक लीटर इथेनॉल अभी 52 .92 रुपये की दर से खरीदती हैं. इस तरह निवेशक को 174 करोड़ रुपये पेट्रोलियम कंपनियों से मिलेंगे.

कार्बन डाइ ऑक्साइड से लाभ

अंत में प्लांट से एक साल में छह हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी. इसे निवेशक दो हजार रुपये प्रति टन बेचेगा. इससे उसे सात करोड़ रुपये हासिल होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं .इस तरह एक निवेशक को मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट से 237 करोड़ रुपये मिलेंगे . उसका कुल औसत खर्च 171 करोड़ होगा.

मुख्य बातें

1. देश में सबसे पहले बिहार में 19 मार्च, 2021 को इथेनॉल पॉलिसी लांच की गयी .
2. 30 जून, 2021 तक 151 निवेश प्रस्ताव आये. प्रस्ताव 30, 382 करोड़ के रहे . इन्हें फर्स्ट विलयरेंस दिया गया.
3. बिहार में 17 इथेनॉल यूनिट के उत्पादन के लिए पेट्रोलियम कंपनियों से करार हुआ.
4. बिहार के लिए 35 .28 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का कोटा निर्धारित किया गया है.
5. बिहार में इथेनॉल की अधिकृत की गयी यूनिट में मुजफ्फरपुर और नालंदा में चार-चर, मधुबनी में दो, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर और बक्सर में एक-एक यूनिट प्रस्तावित हैं . इनमें पूर्णिया की यूनिट शुरू हो चुकी है .

तीन इकाइयां तैयार : राज्य में इथेनॉल उत्पादन की तीन और इकाइयां बन कर तैयार हैं . दो प्लांट गोपालगंज में और एक प्लांट आरा में तैयार है. बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयों में 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का करार हाल ही में तेल विपणन कंपनियों के साथ किया है.

BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

केंद्रीय मंत्री गडकरी व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बीच हुई बैठक में बनी सहमति

दरभंगा व मुजफ्फरपुर रिंग रोड को मंजूरी, गया के लिए आएगी टीम

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजधानी के अलावा अब दरभंगा व मुजफ्फरपुर में भी रिंग रोड बनेगा। केंद्र सरकार ने इन दोनों शहरों में रिंग रोड बनाने पर मुहर लगा दी, जबकि गया और भागलपुर में रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट तय करने के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बीच इस पर सहमति बनी।

बैठक के बाद नितिन नवीन ने बताया कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर चार शहरों के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड बनाने पर चर्चा हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर रिंग रोड की मंजूरी दे दी है, जबकि गया और भागलपुर के एलाइनमेंट पर असहमति है। एलाइनमेंट तय करने के लिए केंद्रीय टीम आएगी। इसके बाद ही इन दोनों शहरों में रिंग रोड बनाने की मंजूरी मिलेगी। मुजफ्फरपुर रिंग रोड का एलाइनमेंट एनएच 77 हाजीपुर-मुजफ्फरपुर से एनएच 28 मुजफ्फरपुर-बरौनी रोड को जोड़ेगा। जबकि भागलपुर में मुंगेर-निर्जाचौकी का हिस्सा रिंग रोड में शामिल होगा।

मंत्री ने वैसी परियोजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की जिसका भूमि अधिग्रहण होना बाकी है। भारतमाला फेज-2 के तहत सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ को जोड़े जाने की चर्चा हुई। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को भागलपुर तक विस्तार करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा एनएच-122, एनएच-331, एनएच-120, एनएच-131बी, एनएच-219, एनएच-319ए के पर्यावरणीय स्वीकृति पर चर्चा हुई। बैठक में पथ निर्माण सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, अभियंता प्रमुख हनुमान प्रसाद चौधरी, मुख्य अभियंता (एनएच) अमरनाथ पाठक, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) नीरज सक्सेना, एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करते पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन।

- भागलपुर में भी रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट तय करने को केंद्र सरकार की टीम आएगी
- अनीसाबाद एलिवेटेड व पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भागलपुर तक विस्तार करने पर हुई चर्चा
- दिल्ली में मिले मंत्री, भागलपुर में मुंगेर-निर्जाचौकी का हिस्सा रिंग रोड में शामिल होगा

एनएच घोषित होंगी 12 सड़कें

बैठक में 12 सड़कों को एनएच घोषित करने पर चर्चा हुई। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अरसा पहले ही इन सड़कों को एनएच घोषित करने की बात कही गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएच घोषित करने के लिए इसे जल्द ही प्लानिंग जोन में भेजा जाएगा जिसकी निगरानी पीएमओ से होती है। इसके बाद औपचारिक प्रक्रिया कर सभी को एनएच घोषित कर दिया जाएगा। एनएच घोषित होने वाली सड़कों में गया के बेलागंज से नालंदा के बलुआ मोड़ होते हुए राजगीर मोड़, जपला-डंगवा-नवीनगर-बारूण, मेहसी-झापा वाया तेतरिया, बरहिमा-अरेराज-सुगौली, भेजा-नुनपट्टी-बंजारी-लौकहा-सिंहेश्वर-चकमाका, गणपतगंज-परवाहा फारबिसगंज वाया प्रतापगंज, बाली-पोठू-माहिदपुर-तुतुरकही-मानिकपुर-शकुरबाद-बभना, कुशेश्वरस्थान-खगड़िया, सकरी-मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना-फुलपरास, मांझी-एकमा-महाराजगंज-बरौली और हाजीपुर-महुआ-ताजपुर शामिल है।

पटना के पहाड़ी में बनेगा मल्टीलेयर जंक्शन

पथ निर्माण मंत्री ने अनीसाबाद से कच्चीदरगाह तक 4-लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा। पीएम पैकेज की एक परियोजना के बदले इस एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। एनएच-30 के पहाड़ी में महात्मा गांधी ब्रिज 4-लेन ब्रिज के बन जाने के बाद एवं निर्माणाधीन नये 4-लेन ब्रिज के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या अधिक होगी। दोनों पुल कुल 8-लेन का होगा तो ट्रैफिक का पूरा दबाव पहाड़ी पर आएगा। इसके मद्देनजर पहाड़ी जंक्शन का विकास करने पर चर्चा हुई। एनएच-119डी पर रामनगर से कच्ची दरगाह के एलाइनमेंट पर भी चर्चा हुई और उसे भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की बात बनी। यह सड़क पटना रिंग रोड का हिस्सा होगा। इसे मल्टीलेयर बनाया जाएगा।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 01.06.2022 | पृष्ठ सं० 1

गंगा चैनल से बढ़ेगी घाट किनारे की खूबसूरती, अभी कलेक्ट्रेट घाट तक बना हुआ है रिवर फ्रंट, इसके विस्तार की तैयारी, छह किमी लंबा होगा

दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक बनेगा गंगा चैनल और पैदल पथ

बदलता पटना

पटना, वरीय संवाददाता। गंगा किनारे दीघा से एएन सिन्हा इंटीट्यूट तक गंगा चैनल और वाक वे यानी पैदल पथ बनेगा। वहां हरित पट्टी विकसित की जाएगी। इससे एएन सिन्हा से दीघा तक के घाटों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे भी आकर्षक हो जाएगा। वर्तमान में सिटी से कलेक्ट्रेट घाट तक रिवर फ्रंट बना हुआ है। वहां घाट किनारे सीढ़ियां बनी हुई हैं। गंगा चैनल और वाक वे की लंबाई करीब छह किमी लंबी होगी। करीब छह साल पहले वर्ष 2016 में भी कुर्जी से गंगा चैनल बनाया गया था लेकिन वर्तमान में इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इसी को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही हरित पट्टी विकसित कर लोगों के टहलने लायक बनाया जाएगा। प्रशासन का प्रयास होगा कि चैनल में गंगा का पानी बहता रहे।

एक्सप्रेस वे होगी सबसे आकर्षक सड़क: गंगा एक्सप्रेस वे एलीवेटेड रोड 21 मीटर चौड़ा है। दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक 40 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। यह पटना शहर की सबसे आकर्षक सड़क होगी। गंगा एक्सप्रेस वे 3831 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे का सात किमी तक काम पूरा हो गया है।

अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण कर दिये निर्देश: पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंगलवार को गंगा एक्सप्रेस का निरीक्षण किया तथा समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया। इंजीनियरों का कहना है कि अटल पथ एक्सटेंशन, अटल पथ रोटरी, एएन सिन्हा आर्म, पीएमसीएच आर्म का काम पूरा हो गया है। पीएमसीएच आने-जाने के लिए अभी एक लेन ही खोली जा रही है। दूसरी लेन में काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि एलसीटी घाट के पास बनने वाले आर्म में अभी समय लगेगा लेकिन यह भी दो माह बाद बनकर तैयार हो जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस वे और अटल पथ को जोड़ने के लिए दीघा के पास बनायी गयी रोटरी। • अरुण अभि

3831 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा गंगा एक्सप्रेस वे

40 मीटर चौड़ी सड़क है दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक

06 साल पहले भी कुर्जी से गंगा चैनल बनाया, अभी अस्तित्व खत्म

07 किलोमीटर के लगभग काम पूरा हो गया है एक्सप्रेस वे का

आकर्षक है अटल पथ रोटरी

अटल पथ और एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए दीघा के पास रोटरी बनायी गयी है। इसका निर्माण अंतिम चरण में है। रात में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। स्ट्रीट लाइट जलते ही दूर से यह आकर्षक लगता है। पटना के लोग परिवार के साथ इसे देखने पहुंच रहे हैं।

एक्सप्रेस वे तैयार होने के बाद देना होगा टोल

पटना, वरीय संवाददाता। पटना में गंगा के किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ (गंगा एक्सप्रेस वे) को काफी सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है लेकिन इस पर चलने वाले वाहन मालिकों को जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। 20.5 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर दो जगहों पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। यहां से गुजरने वाले यात्रियों को यहां टोल देना होगा। हालांकि सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ही टोल की वसूली होगी। 2024 में सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

पुल निर्माण निगम के अधिकारियों का कहना है कि दीघा से दीदारगंज के बीच दो टोल प्लाजा बनेंगे। दोनों के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। पहला टोल प्लाजा एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और एलसीटी घाट के पास बनाई जाने वाली सड़क के आर्म के बीच में होगा। दोनों के लिए जगह छोड़ दी गई है। टोल प्लाजा पर वाहनों को कितना पैसा देना होगा, अभी तय नहीं है। निर्माण एजेंसी लागत के आधार पर यह तय करेगी। दीघा से पीएमसीएच तक सात किमी सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है। 4 जून को एक्सप्रेस वे का शुभारंभ होना है। शेष सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। 2024 में एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जब सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो वाहनों को टोल टैक्स देना होगा।

एक माह तक होगी कड़ी निगरानी

एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार अधिक होगी। इसीलिए एक माह तक पुलिस निगरानी करेगी। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाई स्पीड के स्टीकर और संकेतक लगेंगे। ज्यादातर लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं। इसकी निगरानी की जाएगी, ताकि हादसे को रोका जा सके।

रोटरी को बनाया जाएगा आकर्षक

अटल पथ और एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए दीघा के पास रोटरी बनायी जा रही है। रोटरी होकर ही वाहन अटल पथ से एक्सप्रेस वे तथा एक्सप्रेस वे से अटल पथ पर जा सकेंगे। रोटरी पर लाइटिंग और सड़क की डिजाइन इस प्रकार से बनायी गयी है कि अब यह शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

बाइकर्स से प्रशासन चिंतित: इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। इधर बाइकर्स द्वारा स्टंट किए जाने को लेकर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी काफी चिंतित हैं। ऐसा होने पर एक्सप्रेस वे पर हादसे भी अधिक होंगे। इसीलिए विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन से मदद मांगी है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 01.06.2022 | पृष्ठ सं० 2

सूबे में 1000 मेगावाट पनबिजली का होगा उत्पादन

- पनबिजली की संभावनाओं को तलाशेगा एसजेवीएन
- मिनिमम लोड को घटाने से बिजली खरीद में मिलेगी राहत

> एसजेवीएन बिहार में पनबिजली की संभावनाओं को तलाशेगा। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए कैमूर व अन्य जिलो में 1000 मेगावाट के पंप स्टोरिज स्कीम के लिए कंपनी से करार भी होगा। -बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में एक हजार मेगावाट की पनबिजली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसमें दुर्गावती जलाशय से लेकर अन्य स्थलों पर अध्ययन किया जाएगा। पनबिजली की संभावनाओं की तलाश केंद्र सरकार की ओर से अक्षय ऊर्जा के लिए नामित एजेंसी एसजेवीएन करेगी।

दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जिसमें पम्प स्टोरेज प्लांट परियोजनाएं शामिल हैं, उनके लिए केंद्रीय उपक्रमों को नामित किया है। बिहार में पीएसपी की संभावनाएं तलाशने के लिए एसजेवीएन को नामित किया गया है।

एसजेवीएन को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। गौरतलब है कि पूर्व में बिहार में पीएसपी के लिए कैमूर जिला में शिवाफदार, हथियादह एवं दुर्गावती सहित कई स्थलों को चिह्नित किया गया था। इसी क्रम में एसजेवीएन को कैमूर सहित बिहार के अन्य जगहों पर पम्प स्टोरिज स्कीम के लिए सर्वेक्षण कर इवैल्यूएशन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।

वहीं केंद्र सरकार ने अगले 2 से 3 वर्ष के लिए थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी न्यूनतम लिमिट को 55 फीसदी से घटा कर 40 फीसदी कर दिया है। इससे बिहार को विद्युत खरीद में राहत मिलेगी। साथ ही पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा। टेक्निकल मिनिमम अप न्यूनतम लोड है जिस पर पावर प्लांट प्रचलित मापदंडों में बिना किसी बदलाव के विद्युत उत्पादन कर सकती है। अभी बिहार में करीब 71 फीसदी उत्पादन थर्मल पावर प्लांट द्वारा करता है, जिसकी वजह से नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों द्वारा उत्पादन नहीं कर पाता है। बिहार पिछले दिनों से ही इस मुद्दे को उठा रहा था। इस फैसले से राज्य को महंगी बिजली को सस्ती नवीकरणीय बिजली से बदली जा सकती है। इस फैसले से रिन्यूएबल ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि कोयले का सीमित श्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा ही हमारा भविष्य है। केंद्र सरकार का यह कदम कोयला को संरक्षित करने एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार होगा जिससे हम स्वच्छ जलवायु का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 01.06.2022 | पृष्ठ सं० 06

पटना की विदुषी बनीं मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी 2022 की प्रथम रनअप

मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी जीतने के बाद विदुषी (बीच में)।

सिटी रिपोर्टर. पटना

राजधानी पटना से जुड़ी विदुषी यादव मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी 2022 में प्रथम रनअप बनी हैं। विदुषी का पटना स्थित कंकड़बाग में ननिहाल है। उनकी इस सफलता से पूरे बिहार में खुशी की लहर है। दिल्ली के लीला एंबिएंस होटल में अनु मलिक द्वारा संचालित मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी 2022 कार्यक्रम में गाजियाबाद की मूल निवासी व पटना से जुड़ी विदुषी यादव फर्स्ट रनर अप बनी हैं। साथ ही उन्होंने मिस फ़ोटोजेनिक का ख़िताब भी अपने नाम किया है। विदुषी की मां विनिता यादव का मायके कंकड़बाग में है। विनिता यादव पटना थियेटर की बेहतर रंगकर्मी रही हैं। वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कलाकार रही हैं।

विदुषी यादव मुंबई के सुप्रसिद्ध अभिनेता व फ़िल्म निर्माता रवि यादव की बेटी हैं जो रवि पिक्चर्स के संस्थापक हैं।

3000 लड़कियों में चुनी गई विदुशी

देश भर से करीब 3000 लड़कियां चुनी गई थीं। उनमें से फर्स्ट रनरअप आने पर विदुषी यादव ने कहा कि ये उनके माता पिता, परिवारजनों व बड़ों का आशीर्वाद है। विदुषी मुंबई में रहकर बीएमएम की पढ़ाई कर रही हैं और आने वाले समय में इसी क्षेत्र में रहकर देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करना चाहती है।

ननिहाल में होगा स्वागत

विदुषी के परिवारजनों ने व गाजियाबाद के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने जीतकर घर पहुंचने के बाद विदुषी का भव्य स्वागत किया। ननिहाल में आने पर भी स्वागत समारोह किया जायेगा। इसकी तैयारी की जा रही है।

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 01.06.2022 | पृष्ठ सं० 09

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	42
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	5
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	5
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,24,13,925
⇒ कम से कम एक डोस	7,07,04,068
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	5,99,16,376

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

कतर
दक्षिण कोरिया
जापान
हॉग कॉग
यू.ए.ई.
सिंगापुर
बहरीन
न्यूजीलैंड
कनाडा
यू.एस.ए.
ऑस्ट्रेलिया
सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई
हैदराबाद
पुणे
चेन्नई
नागपुर
गुजरात
कोलकाता
वाराणसी
गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.